

DAILY **CURRENT AFFAIRS**

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 05-09-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

शुक्रवार, 05 सितम्बर, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus :GS 3 : Internal Security / Prelims	केंद्र और मणिपुर सरकार ने कुकी-ज़ो समूहों के साथ शांति समझौता किया
Page 01 Syllabus :GS 3 : Disaster Management / Prelims	एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी-एम शीर्ष पर माननीय मंत्री जी ने इसके समकक्ष धारणा पैरामीटर की आलोचना की
Page 04 Syllabus :GS 1 : Social Issues / Prelims	'भारत की जन्मदर में गिरावट, टीएफआर में 2 साल में पहली गिरावट'
Page 07 Syllabus :GS 2 : Social Justice / Prelims	भारत में एंटीबायोटिक संस्कृति मानसिक स्वास्थ्य को कैसे खतरे में डालती है
Page 10 Syllabus :GS 2 : International Relations / Prelims	भारत-चीन: सीमाकानिर्माण
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus :GS 2 : International Relations	ग्लोबल साउथ के लिए अवसर के रूप में ट्रम्प का टैरिफ युद्ध

केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार ने कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के साथ फिर से बातचीत के बाद कार्रवाई रोक (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर को मणिपुर की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले हुआ है, जो राज्य में लंबे समय से चले आ रहे जातीय संघर्ष और उग्रवाद को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौता न केवल एक सुरक्षा व्यवस्था है, बल्कि शांति, शासन और संघीय अखंडता के लिए संभावित निहितार्थ के साथ एक राजनीतिक कदम भी है।

संधि की मुख्य विशेषताएं

- **संशोधित जमीनी नियम:**
 - कैडरों का सत्यापन और विदेशी राष्ट्रियों को सूची से हटाना, उसके बाद निर्वासन करना।
 - मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की पुनरावृत्ति और विद्रोही शिविरों का स्थानांतरण।
- **मांगों में बदलाव:**
 - पहले की मांग: मणिपुर के भीतर स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद (मई 2023 से पहले)।
 - वर्तमान फोकस: "भारत के संविधान के भीतर बातचीत से राजनीतिक समझौता," जो भविष्य के राजनीतिक संवाद के लिए गुंजाइश छोड़ता है।
- **नागरिक समाज की भूमिका:**
 - कुकी-ज़ो काउंसिल (केजेडसी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग -2 (इंफाल-दीमापुर) खोलने के लिए प्रतिबद्ध किया, जो इंफाल घाटी को नागालैंड और असम से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।
 - हालांकि, मतभेद बने हुए हैं, क्योंकि केजेडसी का दावा है कि राजमार्ग को औपचारिक रूप से कभी अवरुद्ध नहीं किया गया था।

Centre and Manipur govt. ink peace pact with Kuki-Zo groups

Vijaita Singh
NEW DELHI

The Union Home Ministry and the Manipur government signed a Suspension of Operations (SoO) pact with the Kuki-Zo insurgent groups on Wednesday with "re-negotiated terms and conditions or ground rules", the Ministry said on Thursday. The development comes days ahead of Prime Minister Narendra Modi's expected visit to Manipur on September 13, his first visit since ethnic violence between the Kuki-Zo and Meitei people erupted in the State on May 3, 2023.

Security forces will conduct verification of cadres and de-list foreign nationals, if any, the Ministry said. A senior government official said that once identified, the foreign nationals would be deported. The revised ground rules reiterate territorial integrity of Manipur and relocation of camps run by insurgent groups.

Prior to May 3, 2023, the SoO groups demanded autonomous territorial councils within Manipur, but post-violence the demands changed.

Asked if the SoO groups have given up their demand for a separate administration or Union Territory with a legislature, Seilen Haokip, spokesperson Kuki National Organisation (KNO), one of the signatories, told *The Hindu*, "Though the agreement speaks about territorial integrity of Manipur, it also mentions political settlement within the Constitution of India. The Constitution speaks about the integrity of the country, not a district or a State."

He added that "negotiated political settlement within Constitution of India" is a new inclusion in

Core pact

The agreement was signed with 're-negotiated terms and conditions or ground rules'

- The revised ground rules reiterate territorial integrity of Manipur and relocation of camps run by insurgent groups



- The rules also stress need for a negotiated solution to bring lasting peace and stability to the State

the agreement as it was not there in the 2008 text when the demand was for territorial councils in Manipur.

The Kuki-Zo Council (KZC), a conglomerate of civil society organisations, agreed to open the National Highway-2 (Imphal-Dimapur) passing through Kangpokpi district "for the free movement of commuters and essential goods", the Ministry said.

Highway shut

The highway, key to connect the Imphal Valley, where the Meitei people live, to Nagaland and Assam, and critical for the supply of essentials and other commodities, has been shut for the past two years for the movement of the Meitei people.

"The decision came after a series of meetings between officials of MHA and a delegation of KZC in the last few days at New Delhi. KZC has given commitment to cooperate with Security Forces deployed by Government of India (GoI) to maintain peace along NH-02," the government said.

The KZC, however, said that the highway has never been blocked and remained open for commuters and for transportation of essential goods.

राजनीतिक और सुरक्षा महत्व

1. **शांति-निर्माण के प्रयास:** यह समझौता कुकी-ज़ो समूहों और राज्य के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से मई 2023 से मेइतेई समुदाय के साथ जातीय संघर्ष के बाद।
2. **संघीय अखंडता:** मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करके, सरकार का उद्देश्य विखंडन को रोकना है, जबकि अभी भी संवैधानिक वार्ता के लिए जगह की अनुमति है।
3. **सुरक्षा निहितार्थ:** विद्रोही शिविरों का स्थानांतरण और विदेशी नागरिकों (कथित तौर पर म्यांमार से) का निर्वासन सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर करने के लिये महत्वपूर्ण है।
4. **आर्थिक और मानवीय राहत:** इम्फाल घाटी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शृंखलाओं को बहाल करने के लिये NH-2 को फिर से खोलना महत्वपूर्ण है, जिससे मानवीय संकट कम हो जाता है।
5. **प्रतीकात्मक समय:** प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले समझौते पर हस्ताक्षर करना जमीनी स्तर पर प्रगति दिखाने के राजनीतिक इरादे का संकेत देता है।

आगे की चुनौतियां

- **विश्वास की कमी:** कुकी-ज़ो और मेइतेई दोनों समुदाय विभाजित हैं; हिंसा और अविश्वास अभी भी ताजा है।
- **मांगों में अस्पष्टता:** वाक्यांश "बातचीत से राजनीतिक समझौता" अलग-अलग व्याख्याओं को जन्म दे सकता है, संभवतः अलग प्रशासन के लिए कॉल को पुनर्जीवित कर सकता है।
- **कार्यान्वयन बाधाएं:** विद्रोही कैडरों का सत्यापन, शिविर स्थानांतरण, और राजमार्गों पर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना राज्य की क्षमता का परीक्षण करेगा।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** KZC जैसे स्थानीय संगठनों का सहयोग आवश्यक है, लेकिन "नाकाबंदी नहीं" के दावे कथात्मक बेमेल को उजागर करते हैं।

निष्कर्ष

केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो समूहों के बीच शांति समझौता एक गहरे विभाजित राज्य में सुलह के लिए एक सतर्क लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक संवाद की संभावना के साथ सुरक्षा उपायों को जोड़कर, सरकार हाशिए के समूहों की आकांक्षाओं के साथ क्षेत्रीय अखंडता को संतुलित करना चाहती है। हालांकि, वास्तविक शांति मणिपुर में सभी समुदायों के बीच ईमानदारी से कार्यान्वयन, निरंतर संवाद और विश्वास-निर्माण उपायों पर निर्भर करेगी।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में समाचारों में रहे "सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SOO)" समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह भारत सरकार, राज्य सरकारों और विद्रोही समूहों के बीच हस्ताक्षरित युद्धविराम व्यवस्था है।
2. समझौता विद्रोही समूहों को प्रतिबंधों के बिना हथियार बनाए रखने की अनुमति देता है।
3. कुकी-ज़ो समूहों के साथ संशोधित एसओओ समझौता मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को दोहराता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर : c)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: उत्तर-पूर्व में विद्रोह अक्सर पहचान, स्वायत्तता और शासन के मुद्दों में निहित है। चर्चा करें कि कुकी-ज़ो समूहों के साथ हालिया शांति समझौता राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ सुरक्षा अनिवार्यताओं को संतुलित करने की चुनौतियों को कैसे दर्शाता है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Page 01 : GS 3 : Science & Technology / Prelims

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 ने एक बार फिर आईआईटी-मद्रास को लगातार सातवें वर्ष शीर्ष समग्र स्थान पर रखा है, जो भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में प्रमुख केंद्र वित्त पोषित संस्थानों के प्रभुत्व को उजागर करता है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 'सहकर्म धारणा' मानदंड पर चिंता जताई है, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या एनआईआरएफ भारत के शैक्षणिक संस्थानों की विविधता और जमीनी वास्तविकताओं को पर्याप्त रूप से पकड़ पाता है।

NIRF 2025 रैंकिंगकी मुख्य विशेषताएं

- **आईआईटी-मद्रास:** समग्र रूप से पहला स्थान और सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में बरकरार है।
- **आईआईएससी बेंगलुरु:** विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणियों में प्रथम।
- **आईआईएम अहमदाबाद:** छठे वर्ष के लिए प्रबंधन में प्रथम।
- **एम्स नई दिल्ली:** चिकित्सा संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ।
- **अन्य उल्लेखनीय विजेता:**
 - कॉलेजों की श्रेणी में हिंदू कॉलेज (दिल्ली) शीर्ष पर रहा।
 - जामिया हमदर्द (फार्मोसी)।
 - आईआईटी रुड़की (आर्किटेक्चर)।
 - एनएलएसआईयू बेंगलुरु (कानून)।
 - इग्लू (सर्वश्रेष्ठ मुक्त विश्वविद्यालय)।
- **भागीदारी:** रैंकिंग में अब व्यापक संस्थागत भागीदारी के साथ 17 श्रेणियां शामिल हैं, जो भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र के विस्तार को दर्शाती हैं।

चिंताएं और आलोचना

- **सहकर्म धारणा पूर्वाग्रह:**
 - 10% वेटेज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन राज्य संचालित या क्षेत्रीय लोगों पर महानगरीय और केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों का पक्षलिया जाता है।
 - राज्यों ने "क्षेत्रीय पूर्वाग्रह" का आरोप लगाया, क्योंकि दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई में कुलीन संस्थान स्वाभाविक रूप से अधिक ब्रांड दृश्यता का आनंद लेते हैं।

IIT-M tops NIRF rankings; Minister criticises its 'peer perception' parameter

The Hindu Bureau
NEW DELHI

For the seventh straight year, the Indian Institute of Technology (IIT), Madras claimed the top overall position in the higher education rankings announced by the National Institutional Ranking Framework (NIRF) on Thursday. It also remained the country's best engineering college for the 10th straight year.

The NIRF's methodology, however, came in for some criticism from Union Education Minister Dharmendra Pradhan, who presented the India Rankings 2025 awards. He was especially sceptical about the 'peer perception' parameter, that carries 10% of marks for the ranking, and suggested that the NIRF should ensure that government-funded institutions do not fall behind because of this yardstick.

After the 2024 rankings, States and State-run educational institutions had alleged that the rankings reflected "regional bias" as metropolitan education institutions score higher on the 'peer perception' criteria, in comparison to suburban or State-run higher education institutions.

The other parameters that the NIRF currently considers for the overall category are teaching, learning, and resources; research and professional practice; graduation outcomes; and research and inclusivity.

Mr. Pradhan said he was confident that the NIRF would evolve into one of the best accreditation frameworks by including more parameters such as entrepreneurs created by an institution, involving more data-driven approaches, and including



Six IITs make it to the best 10 higher educational institutions in the overall ranking

1	Indian Institute of Technology, Madras
2	Indian Institute of Science, Bengaluru
3	Indian Institute of Technology, Bombay
4	Indian Institute of Technology, Delhi
5	Indian Institute of Technology, Kanpur
6	Indian Institute of Technology, Kharagpur
7	Indian Institute of Technology, Roorkee
8	All India Institute of Medical Sciences, Delhi
9	Jawaharlal Nehru University, Delhi
10	Banaras Hindu University, Varanasi

SOURCE: NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK

more categories and institutions in the future.

In the tenth edition of the NIRF rankings, awards were given in 17 categories and more institutions have joined in the process, he said. "This shows the stable growth of our higher education sector," Mr. Pradhan said, maintaining that the challenge is to increase the number of students and the quality of education in the higher education sector. "Very soon, a new mechanism for institutional ranking will be placed. We will go by the theory of one nation, one data," he noted.

The top 100 institutions in the overall category comprised 24 State universities, 22 private deemed universities, 19 IITs and the Indian Institute of Science (IISc), nine private universities, eight National Institutes of Technology, seven Central universities, five medical institutions, four Indian Institutes of Science Education and Research, one college, and the Indian Agriculture Research Institute.

The IISc, Bengaluru topped the Universities category for the tenth consecutive year and also stood first in the Research Institutions category for the fifth consecutive year. IIM Ahmedabad was the best institution for Man-

agement studies for the sixth consecutive year. The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi occupied the top slot among Medical institutions for the eighth consecutive year.

Jamia Hamdard, New Delhi is the best place for studying Pharmacy and IIT Roorkee retained its top position in Architecture and Planning. Hindu College in Delhi secured the first rank among Colleges for the second consecutive year, replacing Miranda House. The National Law School of India University, Bengaluru retained its first position in Law for the eighth consecutive year.

In the Universities category, IISc ranked first, followed by Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Manipal Academy of Higher Education, Manipal; Jamia Millia Islamia, New Delhi; and University of Delhi, Delhi. Jadavpur University, Kolkata was declared the best among State Public Universities, followed by Anna University, Chennai; Panjab University, Chandigarh; Andhra University, Visakhapatnam; and Kerala University, Thiruvananthapuram.

The Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi was the best among Open Universities.

- **इकिटी बनाम उत्कृष्टता बहस:**

- केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान शीर्ष स्लॉट पर हावी हैं, जबकि बड़ी छात्र आबादी वाले कई राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का प्रतिनिधित्व कम है।
- यह सवाल उठाता है कि क्या रैंकिंग व्यापक-आधारित सुधार को प्रोत्साहित करने के बजाय मौजूदा पदानुक्रमों को सुदृढ़ करती है।

- **मापदंडों को विकसित करने की आवश्यकता:**

- मंत्री ने नए संकेतकों को शामिल करने का सुझाव दिया जैसे:
 - सृजित उद्यमियों की संख्या।
 - नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति।
 - व्यापक डेटा-संचालित विश्लेषण ("एक राष्ट्र, एक डेटा")।
- वर्तमान ढांचा शिक्षण, सीखने, संसाधनों, अनुसंधान, स्नातक परिणामों, समावेशिता और धारणा पर जोर देता है।

उच्च शिक्षा के लिए निहितार्थ

1. **नीतिगत बदलाव की उम्मीद:** सरकार की आलोचनाओं को दूर करने और इसे अधिक समावेशी बनाने के लिये रैंकिंग प्रणाली को संशोधित करने की योजना है।
2. **वैश्विक बेंचमार्किंग:** एक अधिक मज़बूत NIRF अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है, वैश्विक छात्रों और सहयोगों को आकर्षित कर सकता है।
3. **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना:** रैंकिंग संस्थानों को गुणवत्ता, अनुसंधान और परिणामों में सुधार करने के लिये प्रेरित करती है, लेकिन मापदंडों की निष्पक्षता महत्वपूर्ण है।
4. **पहुँच में समानता:** संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिये राज्य और ग्रामीण संस्थानों को उजागर करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग आईआईटी-मद्रास और आईआईएससी जैसे कुलीन संस्थानों की अकादमिक उत्कृष्टता की पुष्टि करती है, लेकिन भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक चुनौतियों को भी उजागर करती है। जबकि रैंकिंग प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनकी कार्यप्रणाली को समावेशिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रस्तावित सुधार - जैसे उद्यमिता, नवाचार और "एक राष्ट्र, एक डेटा" को शामिल करना - एनआईआरएफ को वास्तव में व्यापक और विश्व स्तर पर सम्मानित ढांचा बना सकता है। अंततः, भारत का लक्ष्य उत्कृष्टता के साथ समानता को संतुलित करना होना चाहिए, जिससे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों का उत्थान सुनिश्चित हो।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है (एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग)?

1. इंजीनियरिंग - आईआईटी मद्रास
2. प्रबंधन – आईआईएम अहमदाबाद
3. विश्वविद्यालय – जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
4. मेडिकल – एम्स, नई दिल्ली

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : a)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने में एनआईआरएफ जैसी संस्थागत रैंकिंग के महत्व पर चर्चा करें। सभी क्षेत्रों में समावेशिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ढांचे में सुधार कैसे किया जा सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

नमूनापंजीकरणसर्वेक्षण (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव पर प्रकाश डालती है: भारत की अशोधित जन्म दर (CBR) वर्ष 2022 में 19.1 से घटकर वर्ष 2023 में 18.4 हो गई है, जबकि कुल प्रजनन दर (TFR) दो वर्षों में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे गिरकर 1.9 हो गई है। यह भारत के चल रहे जनसांख्यिकीय संक्रमण और जनसंख्या वृद्धि, श्रम शक्ति और सामाजिक नीति के लिए इसके संभावित प्रभावों का संकेत देता है।

India's birth rate down, first dip in TFR in 2 years'

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

India's Crude Birth Rate (CBR), the number of children born per 1,000 people in the population in a year, has declined 0.7-points from 19.1 in 2022 to 18.4 in 2023. The country's Total Fertility Rate (TFR) has fallen for the first time in two years to 1.9 in 2023, according to the latest Sample Registration Survey Statistical Report for 2023. In 2021 and 2022, India's TFR remained constant at 2.0.

The report, released by the Office of the Registrar General of India this week, revealed that the highest CBR was in Bihar at 25.8, and the lowest was in Tamil Nadu at 12. Bihar reported the highest TFR (2.8) among the bigger States and Union Territories (UTs), and Delhi reported the lowest (1.2).

The report pointed out that 18 States and UTs had

The latest data was sourced from Sample Registration Survey Statistical Report released this week

reported a TFR of below the replacement level TFR of 2.1. Replacement level TFR denotes the average number of children each woman needs to give birth for one generation to replace the other.

The RGI released the Civil Registration System (CRS), Sample Registration System (SRS), and Medical Certification of Cause of Death (MCCD) reports for 2021 after a four-year delay in May this year, and in June, the SRS, CRS, and MCCD data for 2022 were released. While the SRS for 2023 has been made public, the corresponding CRS and MCCD datasets are yet to appear on the Census website.

The SRS 2023 datasets

showed that the proportion of the elderly in the country (people above 60) rose by 0.7 percentage points in a year to 9.7% of the population. Kerala has the highest proportion of elderly population at 15%. Assam (7.6%), Delhi (7.7%), and Jharkhand (7.6%) reported the lowest proportion of their respective populations to be above 60.

The TFR data, which denotes the average number of children expected to be born per woman during her entire span of reproductive period, further showed that all States reporting TFR that is higher than replacement level were in northern India - Bihar (2.8), Uttar Pradesh (2.6), Madhya Pradesh (2.4), Rajasthan (2.3), and Chhattisgarh (2.2). The States and UTs reporting the lowest TFR included Delhi (1.2), West Bengal (1.3), Tamil Nadu (1.3), and Maharashtra (1.4).

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **राष्ट्रीय औसत:**
 - सीबीआर: 18.4 (2023) बनाम 19.1 (2022)।
 - TFR: 1.9 (2023), 2.0 (2021 और 2022) से नीचे।
- **राज्य विविधताएं:**
 - **उच्चतम CBR & TFR:** बिहार (CBR – 25.8, TFR – 2.8)।
 - **सबसे कम सीबीआर:** तमिलनाडु (12)।
 - **सबसे कम टीएफआर:** दिल्ली (1.2)।
 - उत्तरी राज्य (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़) अभी भी प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं।
 - दक्षिणी और पश्चिमी राज्य (तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली) प्रतिस्थापन के नीचे अच्छी तरह से।
- **वृद्ध जनसंख्या:**
 - बुजुर्ग (60+) अब 9.7% आबादी, एक वर्ष में 0.7% ऊपर।
 - केरल में बुजुर्गों का अनुपात सबसे अधिक (15%) है, जबकि असम, दिल्ली, झारखंड में सबसे कम (~ 7.6-7.7%) रिपोर्ट है।
- **डेटा अंतराल:** वर्ष 2023 के लिये CRS और MCCD डेटासेट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे पूर्ण जनसांख्यिकीय मूल्यांकन धीमा हो गया है।

विश्लेषण और निहितार्थ

1. **जनसांख्यिकीय संक्रमण**
 - भारत व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं के साथ प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन क्षमता के करीब पहुंच गया है।
 - दक्षिणी और पश्चिमी राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण और उम्र बढ़ने का अनुभव कर रहे हैं, जबकि उत्तरी राज्य अभी भी समग्र जनसंख्या गति को चलाते हैं।
2. **आर्थिक और सामाजिक प्रभाव**
 - प्रजनन क्षमता में गिरावट जनसंख्या वृद्धि दर को कम करती है, जिससे भविष्य में श्रम आपूर्ति प्रभावित होती है।
 - बुजुर्गों की बढ़ती हिस्सेदारी से पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की मांग बढ़ेगी।
 - युवा जनसंख्या लाभ ("जनसांख्यिकीय लाभांश") उम्मीद से पहले कम हो सकता है यदि नौकरियां, कौशल और उत्पादकता संरक्षित नहीं हैं।
3. **क्षेत्रीय विभाजन**
 - उत्तरी राज्यों में उच्च प्रजनन क्षमता प्रवासन दबाव पैदा कर सकती है, जबकि दक्षिणी राज्यों में कम प्रजनन क्षमता से श्रम की कमी और वृद्ध समाज हो सकते हैं।
 - यह अंतर-राज्य आर्थिक और राजनीतिक तनाव (जैसे, परिसीमन पर बहस, राजकोषीय हस्तांतरण) को तेज कर सकता है।

4. नीतिगत चुनौतियाँ

- 4 कमप्रजननवाले राज्यों में जनसंख्या-नियंत्रण नीतियों को जन्म के समान उपायों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता।
- जराचिकित्सा देखभाल बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण का विस्तार।
- शिक्षा, कौशल-निर्माण और रोजगार सृजन के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता वाले राज्यों में युवाओं का लाभ उठाना।

निष्कर्ष

भारत की टीएफआर का 1.9 तक गिरना एक ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि देश धीमी जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती उम्र बढ़ने की आबादी के चरण में प्रवेश कर रहा है। जबकि यह सतत विकास और बेहतर संसाधन आवंटन के अवसर प्रदान करता है, यह क्षेत्रीय असंतुलन, प्रवासन और बुजुर्गों की देखभाल की चुनौतियों को भी जन्म देता है। नीति निर्माताओं को एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए – उत्तर में जनसंख्या स्थिरीकरण और दक्षिण में उम्र बढ़ने और श्रम-बल की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना – यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण एक दायित्व के बजाय एक ताकत बन जाए।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) 2023 के अनुसार भारत के जनसांख्यिकीय रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है।
2. बिहार प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक टीएफआर रिपोर्ट करता है, जबकि दिल्ली सबसे कम रिपोर्ट करता है।
3. केरल में देश में बुजुर्ग आबादी का अनुपात सबसे अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 1 और 3 |
| (c) केवल 2 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

उत्तर : d)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश अपेक्षा से अधिक तेजी से घट रहा है। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्षों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के खिलाफ भारत की लड़ाई को काफी हद तक सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोग संकट के रूप में तैयार किया गया है। हालांकि, उभरते शोध से कम चर्चा वाले आयाम का पता चलता है - आंत-मस्तिष्क अक्ष के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर एंटीबायोटिक अति प्रयोग का प्रभाव। यह एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को न केवल एक चिकित्सा खतरे के रूप में, बल्कि मनोवैज्ञानिक रुग्णता के योगदानकर्ता के रूप में भी फिर से अवधारणा करने की आवश्यकता को बढ़ाता है, विशेष रूप से एक ऐसे देश में जो पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल से जूझ रहा है।

How the antibiotic culture in India imperils mental health

While threat of antimicrobial resistance is acknowledged as a formidable public health hazard, its implications on mental well being remain under examined; public health campaigns must pivot towards education and empowerment and regulatory reform is imperative to address the issue

Rashikhha Ra Iyer

As mental health awareness gains momentum in India, a surreptitious menace is insidiously undermining this edifice of progress: the unbridled use of antibiotics. Whilst the threat of antimicrobial resistance (AMR) is ubiquitously acknowledged as a formidable public health hazard, its profound implications on mental well being remain under examined. At the epicentre of this conundrum lies the intricate gut-brain axis – a labyrinthine communication nexus between the gastrointestinal apparatus and the cerebral cortex.

Nascent research suggests that perturbations in gut microbiota, frequently precipitated by overzealous antibiotic consumption, may significantly contribute to the aetiology of anxiety, depression, and cognitive degeneration. In a country where antibiotics are often taken sans prescription or medical oversight, this gut-brain axis nexus demands an urgent and paradigmatic shift in attention for remedial measures to mitigate this silent yet calamitous crisis.

Antibiotic consumption
India occupies a distressing prominence in the global hierarchy of antibiotic consumption. The trilemma of over-the-counter accessibility, rampant self-medication, and limited public awareness has cultivated an entrenched culture of antibiotic overutilization. According to the Institute for Health Metrics and Evaluation, antimicrobial resistance (AMR) was accountable for an estimated 2.67,000 fatalities in India in 2021, with projections forecasting an escalation to 1.2 million by 2030, should prevailing trends continue.

A seminal study published in 2022 in *The Lancet Regional Health - Southeast Asia* revealed a disquieting statistic: nearly half of all antibiotics consumed in India comprised unapproved formulations, exacerbating the threat of resistance. This egregious misuse not only fuels the conflagration of AMR but also precipitates a deleterious impact on the gut's microbial diversity – a vital constituent of mental well being.

What's in the gut
The gastrointestinal tract harbours trillions of microorganisms that exert a profound influence on the biosynthesis of pivotal neurotransmitters, including serotonin and dopamine. These chemical messengers orchestrate the regulation of mood, sleep-wake cycles, and stress responses, and so, the gut plays an integral role in maintaining neurological homeostasis. When antibiotics disrupt this delicate microbial equilibrium, the repercussions can resonate throughout the nervous system, potentially precipitating a cascade of downstream effects.

Pioneering research from institutions such as the National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) and the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) has initiated an exploration of the intricate relationship between gut dysbiosis and psychiatric maladies. Although the scientific discourse is still evolving, the



In focus:
Students raising awareness about antimicrobial resistance. NIT PHOTO

accumulating evidence is sufficiently compelling to justify the implementation of targeted public health interventions towards a proactive and informed response to mitigate the burgeoning threat of gut-related psychiatric disorders.

The ramifications of microbial perturbation extend beyond mere biochemical imbalances; they encompass a broader psychosocial dimension that implicates the very fabric of human experience. The gut microbiota, often romanticised as the "second brain," is not merely a passive consortium of bacteria, but an active participant in neurochemical symphony. Through the production of short-chain fatty acids, modulation of the immune system, and interaction with the vagus nerve, these microorganisms wield influence over neurodevelopmental trajectories and behavioural phenotypes.

Indeed, the burgeoning field of psychobiotics – a portmanteau term coined to describe probiotics and prebiotics that confer mental health benefits – has illuminated the therapeutic potential of modulating gut flora to ameliorate psychiatric symptoms. A 2020 meta-analysis published in *Frontiers in Psychiatry* revealed that probiotic supplementation was associated with significant reductions in depressive symptoms, particularly among individuals with mild to moderate depression. Such findings underscore the plausibility of gut-targeted interventions as adjuncts to conventional psychiatric care, especially in a nation like India where mental health infrastructure remains woefully inadequate.

Compounding this crisis is the paucity of public awareness regarding the gut-brain axis and its susceptibility to pharmacological insult. The average Indian consumer, often bereft of access to nuanced medical counsel, remains oblivious to the long-term consequences of indiscriminate antibiotic use. The cultural proclivity towards "quick fixes" and the valorisation of pharmaceutical interventions over lifestyle modifications further entrench this paradigm. In rural and semi-urban locales, where healthcare

access is fragmented and regulatory oversight lax, antibiotics are dispensed easily, and without prescription – frequently for viral infections where they are not only ineffective but actively deleterious.

Moreover, the economic incentives that drive antibiotic over-prescription cannot be ignored. Private practitioners, operating within a fee-for-service model, may be inclined to prescribe antibiotics to appease patient expectations or expedite symptomatic relief. Pharmacies, often unregulated, serve as de facto dispensaries, offering potent medications without requisite prescriptions. This confluence of systemic vulnerabilities and behavioural predispositions has rendered India a fertile ground for AMR proliferation and microbial dysbiosis.

The implications for mental health are manifold. Dysbiosis-induced inflammation has been implicated in the pathogenesis of major depressive disorder, with elevated levels of pro-inflammatory cytokines such as IL-6 and TNF-alpha observed in affected individuals. These inflammatory mediators can traverse the blood-brain barrier, altering neurotransmitter metabolism and neuroplasticity. Furthermore, gut-derived metabolites like butyrate and propionate have been shown to influence gene expression in the brain, modulating synaptic function and stress reactivity.

Need for interventions

In this context, the intersection of microbiology and psychiatry assumes profound significance. It invites a reconceptualisation of mental illness – not merely as a cerebral aberration but as a systemic dysfunction with gastrointestinal antecedents. Such a paradigm shift necessitates interdisciplinary collaboration, integrating gastroenterology, psychiatry, nutrition, and public health to forge holistic interventions.

Encouragingly, India possesses a rich repository of traditional knowledge that can be harnessed to promote gut health. Fermented foods – ubiquitous in Indian

cuisine – such as curd, idli, dosa, and pickles, serve as natural probiotics, fostering microbial diversity and resilience.

Public health campaigns must pivot towards education and empowerment. The National Health Mission and Ayushman Bharat can incorporate gut-brain literacy into their outreach programmes, elucidating the dangers of antibiotic misuse and the virtues of dietary modulation. School curricula can embed modules on microbiome science, cultivating a generation of informed citizens. Media platforms, both traditional and digital, can amplify narratives that valorise microbial stewardship and mental wellbeing.

Simultaneously, regulatory reform is imperative. The Central Drugs Standard Control Organization must enforce stringent controls on antibiotic dispensation, mandating prescription-only access and penalising non-compliance. More surveillance systems such as INSAR (Indian Network for Surveillance of Antimicrobial Resistance), which is now part of a broader network, should be created and integrated with mental health metrics to elucidate correlations and inform policy. Investment in microbiome research, particularly within Indian populations, can yield context-specific insights and therapeutic innovations.

Clinicians, too, must recalibrate their praxis. Antibiotic stewardship should be embedded within medical training, sensitising practitioners to the collateral damage of pharmacological interventions. Psychiatric evaluations can incorporate gastrointestinal assessments, recognising the bidirectional interplay between gut and mind. Nutritional counselling, often relegated to ancillary status, must be foregrounded. As India strides towards a more enlightened discourse on mental health, it must not overlook the microbial foundations of well being.

(Rashikhha Ra Iyer is a multidisciplinary clinician working in the U.K., specialising in the delivery of clinical interventions in forensic settings. Rashikhha.RaIyer@outlook.com)

मुख्य चिंताएं

- **भारत में उच्च एंटीबायोटिक खपत**
 - भारत एंटीबायोटिक दवाओं के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है।
 - आसान ओवर-द-काउंटर पहुंच, स्व-दवा, और अनियमित फार्मेशियों का दुरुपयोग होता है।
 - वर्ष 2022 के लैंसेट अध्ययन में पाया गया कि भारत में उपयोग किए जाने वाले लगभग 50% एंटीबायोटिक्स अस्वीकृत फॉर्मूलेशन थे।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)**
 - 2021 में अनुमानित 2.67 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार; 2030 तक 1.2 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है।
 - कमजोर विनियमन और आर्थिक प्रोत्साहन अति-नुस्खे को प्रोत्साहित करते हैं।
- **आंत-मस्तिष्क अक्ष व्यवधान**
 - एंटीबायोटिक्स आंत माइक्रोबायोटा को परेशान करते हैं, जो मूड, अनुभूति और तनाव विनियमन के लिए आवश्यक सेरोटोनिन, डोपामाइन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करते हैं।
 - आंत डिस्बिओसिस अवसाद, चिंता और संज्ञानात्मक गिरावट से जुड़ा हुआ है।
 - निमहांस और एम्स के अध्ययन भारत में आंत-मनोरोग संबंधों के शुरुआती प्रमाण दिखाते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव**
 - डिस्बिओसिस-प्रेरित सूजन और साइटोकिन रिलीज (जैसे, आईएल -6, टीएनएफ-अल्फा) मस्तिष्क में पार कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टी को बदल सकते हैं।
 - माइक्रोबियल विविधता का नुकसान मनोवैज्ञानिक विकारों के खिलाफ लचीलापन कम करता है।
 - साइकोबायोटिक्स (चिकित्सा के रूप में प्रोबायोटिक्स / प्रीबायोटिक्स) में बढ़ती रुचि उपचार के रास्ते पर प्रकाश डालती है।

नीति और प्रणालीगत चुनौतियां

1. **सांस्कृतिक आदतें:** त्वरित-फिक्स एंटीबायोटिक निर्भरता, दीर्घकालिक नुकसान के बारे में कम जागरूकता।
2. **कमजोर विनियमन:** आसान फार्मसी पहुंच, केवल पर्चे के नियमों का खराब प्रवर्तन।
3. **स्वास्थ्य देखभाल प्रोत्साहन:** डॉक्टर रोगी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक लिख सकते हैं।
4. **मानसिक स्वास्थ्य ब्लाइंड स्पॉट:** वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रवचन शायद ही कभी मनोरोग देखभाल में माइक्रोबायोम विज्ञान को एकीकृत करता है।

आगे की राह

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान:**
 - आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आंत-मस्तिष्क साक्षरता को एकीकृत करें।
 - आंत स्वास्थ्य (जैसे, पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थ) का समर्थन करने वाले आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना।
 - स्कूल पाठ्यक्रम में माइक्रोबायोम जागरूकता शामिल करें।

- **नियामक सुधार:**
 - एंटीबायोटिक बिक्री पर सख्त नियंत्रण और अवैधवितरणकादंड।
 - मानसिकस्वास्थ्यपरिणामोंके साथ-साथ AMR को ट्रैक करने के लिये INSAR जैसी निगरानी प्रणालियों का विस्तार करना।
- **नैदानिक अभ्यास:**
 - चिकित्सा प्रशिक्षण में एंटीबायोटिक प्रबंधन को शामिल करें।
 - आकलन में आंत के स्वास्थ्य पर विचार करने के लिए मनोचिकित्सकों को प्रोत्साहित करें।
 - पोषण संबंधी परामर्श को मनोरोग देखभाल का अभिन्न अंग बनाएं।
- **अनुसंधान और नवाचार:**
 - भारत-विशिष्ट माइक्रोबायोम अध्ययनों में निवेश करें।
 - पारंपरिक उपचार के सहायककेरूपमेंसाइकोबायोटिकउपचारोंकाअन्वेषणकरें।

निष्कर्ष

भारत में एंटीबायोटिक कल्चर, यदि अनियंत्रित किया जाता है, तो दोहरे संकट पैदा होने का जोखिम है: बढ़ता रोगाणुरोधी प्रतिरोध और बिगड़ता मानसिक स्वास्थ्य। आंत को "दूसरे मस्तिष्क" के रूप में पहचानना एक अंतःविषय दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो सूक्ष्म जीव विज्ञान, मनोचिकित्सा, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोड़ता है। इसलिए, एएमआर के खिलाफ भारत की लड़ाई को संक्रामक रोग प्रबंधन से परे विस्तारित करना चाहिए ताकि इसकी आबादी के मनोवैज्ञानिक लचीलेपन और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंत-मस्तिष्क अक्ष की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, जिसे अक्सर स्वास्थ्य अनुसंधान में देखा जाता है?

- (a) प्रतिरक्षा प्रणाली और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली
- (b) अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बीच हार्मोनल लिंक
- (c) जठरांत्र प्रणाली और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच द्विदिश संचार
- (d) रीढ़ की हड्डी और आंतों के बीच तंत्रिका संबंध

उत्तर : (c)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को संबोधित करने में विनियमन, जागरूकता और नैदानिक प्रथाओं की भूमिका की जांच करें। मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के साथ संक्रामक रोग प्रबंधन को संतुलित करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव दें। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

भारत-चीन सीमा का सवाल एशिया के सबसे जटिल और स्थायी विवादों में से एक है, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक विरासत और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों में निहित हैं। अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के विपरीत, हिमालय की अधिकांश सीमा ऐतिहासिक रूप से अनिश्चित थी, जिसे ब्रिटिश कार्टोग्राफी और तिब्बती आधिपत्य द्वारा आकार दिया गया था। आजादी के बाद भारत ने ब्रिटिशकाल के मानचित्रों को पवित्र मानने पर जोर दिया, जबकि चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण मजबूत करने के बाद उन्हें खारिज कर दिया और अपने दावों को आगे बढ़ाया। धारणा में इस विचलन ने दशकों के संघर्ष, वार्ता और असहज शांति का उत्पादन किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संघर्ष

- **औपनिवेशिक विरासत:** सीमा दो साम्राज्यों - ब्रिटिश भारत और किंग राजवंश का एक उत्पाद थी। निर्जन हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण, यह अनुचित रूप से सीमांकित रहा।
- **पूर्वी क्षेत्र:** भारत ने अपना दावा वर्ष 1914 के शिमला कन्वेंशन पर आधारित किया, जिसने मैकमोहन रेखा का निर्माण किया। हालांकि, चीन ने इस समझौते को कभीस्वीकार नहीं किया।
- **पश्चिमी सेक्टर (अक्साई चिन):** किसी भी पक्ष की स्थायी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन चीन ने शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला एक रणनीतिक राजमार्ग बनाया। यहां नियंत्रण का दावा करने के भारत के देर से किए गए प्रयासों के कारण तनाव में वृद्धि हुई।
- **1962 का युद्ध:** चीन ने अक्साई चिन के बदले भारत के पूर्वी दावों की मान्यता सहित समझौतों की पेशकश की, लेकिन भारत ने उन्हें खारिज कर दिया। संघर्ष के परिणामस्वरूप चीन ने मैकमोहन रेखा के पूर्व में पीछे हटते हुए अक्साई चिन को बनाए रखा।

India-China: the making of a border

Being high up in the Himalayas, in a largely unpopulated area, the India-China border has been largely indeterminate and inaccurate. While at present peace and tranquillity at the boundary is what is important, the issue is far from being resolved

WORLD INSIGHT

Manoj Joshi

India has a complicated history with regards to its border with China. The border was the product of two empires – the Manchu and the British. Being in the Himalayas and in an unpopulated area, it was not precise.

After independence, it would have been prudent for both countries to sit and lay down a precise and accurate border. Unfortunately, India took the position that it knew where the border was and that there was no need for negotiations. The Indian position was based on its confidence in British-era maps, but not on actual control on the ground.

The beginning of the conflict

While neither India nor China had a permanent presence in the Aksai Chin, a barren, high-altitude desert, China in order to facilitate its control of Tibet built a highway through the Aksai Chin from Xinjiang and occupied it. Similarly, in the east, India established control over Tawang, a major monastery town in what is now Arunachal Pradesh. It did so on the basis of the fact that it had signed a border agreement with Tibet in 1914, at a time when Tibet had been independent, which defined the boundary by the so-called McMahon Line.

The Chinese suggested various ways to deal with what they said was an undefined border. In 1959, they proposed that the two sides accept a Line of Actual Control as the border and move forces 20 kms back from it. In 1960, Zhou Enlai, former Premier of China, came to New Delhi and proposed a swap where India would concede the Chinese position in Aksai Chin in exchange for Chinese acceptance of India's claim over Arunachal Pradesh.

However, India refused. When India belatedly tried to recapture Aksai Chin, it led to friction with China and eventually resulted in the 1962 India-China war. After the war, the Chinese withdrew to the areas north of the McMahon Line in the east, but in the west (Ladakh), they retained some areas they had captured in the war.

Post war developments

For nearly one and a half decades, both sides stayed away from the border. In 1975, India constituted a High Level China Study Group to monitor the Sino-Indian border. It was under the direction of this body that the border was mapped with satellite imagery, and Indian police/army patrols were ordered to regularly police the border by establishing patrolling points along it.

In February 1979, Atal Bihari Vajpayee, who was the foreign minister of the then Janata Party government, visited Beijing and became the first senior Indian leader to go there since the war. Vajpayee, a veteran parliamentarian, had been a critic of Nehru's China policy. But in 1979, he saw his mission as one to restore normalcy with India's two neighbours, Pakistan and China. Though his visit had to be cut short because of the Chinese invasion of Vietnam, it did succeed in restoring a degree of normalcy in India-China ties. The Chinese motivation for accepting the Indian outreach was to ensure that New Delhi did not get too close to the Soviet Union which, at the time, viewed as China's principal antagonist.

Deng Xiaoping, China's supreme leader, suggested a revival of the 1960 Zhou Enlai visit. In June 1980, in an



New relations: Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru greeting Zhou Enlai, the Chinese Premier, on his arrival in New Delhi, on April 19, 1960. (HINDU ARCHIVES)

Interview with Krishan Kumar, Editor of *Vibrant*, a now defunct defence journal, Deng said that China could recognise the McMahon Line if India was willing to recognise the existing status quo. The Chinese repeatedly tried to push this proposal but the Indian government, now headed by Indira Gandhi, comprised of officials who had not forgiven China for the 1962 "betrayal", saw this as an effort to trade a chunk of Indian territory for another.

In 1983, the Chinese went a step further and proposed not just a swap, but also that India should concede areas their forces had captured in 1962 in Ladakh. This proposal was named the 'LAC Plus', and it also was not accepted by the Indian government.

A time for negotiations

Nevertheless, the two sides resumed their border talks with the first round being held in December of 1981. The initial talks did not yield much. The Chinese pushed their package deal, while India pushed the talks to be held sector by sector. Therefore, the two sides were unable to come to an agreement. By the fifth round of talks in September 1984, the Indian side felt that the Chinese were coming around to their view, but they were mistaken. Even as the sixth round began in November 1985, Chinese Vice-Minister Lin Shaoqing informed his Indian counterpart, Secretary (East) A.P. Venkateswar, that there was a bigger dispute in the eastern sector, and that India would have to make unspecified concessions here for the Chinese to be

able to give concessions in the west. Though they did not state it at the time, they were demanding that India concede the Tawang tract as part of the settlement.

The demand for Tawang was more fundamental, and represented a shift in China's domestic Tibet policy since the monastery was a major centre of Tibetan Buddhism and the area around it had been controlled by Tibet till well after the 1914 agreement.

Further on, Indian and Chinese troops clashed on the border in Nathu La and Cho La in Sikkim in 1967, but things settled down thereafter. In 1975, Sikkim was incorporated into the Indian Union, an action that led to Chinese protests.

In 1983, as part of a reset of the overall Indian security posture against China, Indian officials began visiting Wuyangling in the region of the Namka Chu river where the first clashes of the 1962 war had occurred. In 1986, the Chinese occupied this region and triggered a crisis that saw the forward deployment of Indian forces at a pass overlooking Wuyangling. Under Operation Falcon, India moved its forces forward along the entire LAC. The Chinese response was haphazard as they were clearly taken aback by this development. In any case, the two sides soon reached an agreement to de-escalate the situation. But the crisis did reveal that the Indian Army was now very different from the force that suffered disaster in 1962.

Move towards complete normalcy

By 1985, it was clear to the United States and the Soviet Union that the threat had reduced

because of their misadventure in Afghanistan. Now in order to check India's increasing closeness to the U.S., China invited Rajiv Gandhi to Beijing as a return for Zhou's 1960 Delhi visit. The Gandhi visit to China in December 1988 was seen as the beginning of the true normalisation of ties that had been sundered by the 1962 war. Deng told Rajiv "let both sides forget the unpleasant period in our past relations." The two sides agreed to restore, improve and develop good neighbourly relations.

As for the border, Premier Li Peng stated that it should be settled on the basis of mutual understanding and mutual accommodation (MUMA). Rajiv Gandhi's response to this was that there should be a "fair and reasonable... mutually acceptable solution to this question." In the meantime, the two sides agreed to develop bilateral relations in other fields which would create the conditions for a "fair and reasonable" settlement of the boundary issue.

This was a decisive break from the past, since till then India had insisted that without the settlement of the boundary issue, there could be no normalisation of ties. This situation suggested that the priority was to maintain peace and tranquillity on the borders. The two countries then eventually re-designated the meeting of their officials as a "joint working group" (JWG) on the border issue to work together for a settlement.

Manoj Joshi is a Distinguished Fellow, Observer Research Foundation, New Delhi. This is the first in a three part series on India-China border relations.

THE GIST

While neither India nor China had a permanent presence in the Aksai Chin, a barren, high-altitude desert, China in order to facilitate its control of Tibet built a highway through the Aksai Chin from Xinjiang and occupied it.

In 1960, Zhou Enlai, former Premier of China, came to New Delhi and proposed a swap where India would concede the Chinese position in Aksai Chin in exchange for Chinese acceptance of India's claim over Arunachal Pradesh.

When India belatedly tried to recapture Aksai Chin, it led to friction with China and eventually resulted in the 1962 India-China war.

युद्ध के बाद के घटनाक्रम

- **फ्रीज एंड सतर्कतापूर्ण जुड़ाव (1962-79):** लगभग 15 वर्षों तक दोनों पक्ष सीमा से बचते रहे। भारत ने चीन अध्ययन दल का गठन किया और गश्त को सुदृढ़ किया।
- **राजनीतिक पहुंच:** वाजपेयी की 1979 की यात्रा और देंग जियाओपिंग की 1980 में "अदला-बदली" प्रस्ताव को पुनर्जीवित करना सामान्यीकरण के प्रयासों का संकेत था, लेकिन भारत ने 1962 के "विश्वासघात" का हवाला देते हुए उन्हें खारिज कर दिया।
- **सैन्य मुद्रा:** 1980 के दशक में वांगडुंग और अन्य जगहों पर भड़क उठी। ऑपरेशन फाल्कन (1986) ने 1962 की तुलना में भारत की बेहतर सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन किया।

बातचीत के प्रयास और बदलाव

- **1981-88 सीमा वार्ता:** जबकि चीन ने एक पैकेज डील (स्वैप) को प्राथमिकता दी, भारत ने सेक्टर-दर-सेक्टर दृष्टिकोण की मांग की। बीजिंग द्वारा तिब्बत के लिए इसके महत्व का हवाला देते हुए तवांग में रियायतों के लिए दबाव डालने के कारण वार्तारूकगई।
- **राजीव गांधी की 1988 की बीजिंग यात्रा:** एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि भारत ने सीमा चर्चा के समानांतर द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण को स्वीकार किया। संयुक्त कार्य समूह (JWG) के निर्माण ने प्रक्रिया को संस्थागत बना दिया।
- **MUMA (आपसी समझ और आपसी आवास) का सिद्धांत:** दोनों पक्ष अन्य क्षेत्रों में सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का प्रबंधन करने पर सहमत हुए।

महत्व और सबक

1. **औपनिवेशिक विरासत बनी रहती है:** विवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि औपनिवेशिक युग की कार्टोग्राफी ने अस्पष्ट सीमाओं को कैसे छोड़ा, विशेष रूप से कम आबादी वाले उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में।
2. **चूके हुए अवसर:** 1950-60 के दशक में भारत के कठोर रुख ने यकीनन शुरुआती समझौता समाधानों को रोक दिया, जिससे अविश्वास गहरा गया।
3. **रणनीतिक गणना:** चीन के प्रस्ताव अक्सर इसकी व्यापक भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं (जैसे, सोवियत संघ का मुकाबला करना, अमेरिका-भारत निकटता का प्रबंधन)।
4. **टकराव से प्रबंधन तक:** राजीव गांधी-देंग ज़ियाओपिंग की समझ ने शांति और शांति बनाए रखने के लिए संकल्प से ध्यान केंद्रित किया – एक टेम्पलेट जो 1990 के दशक से समझौतों को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

भारत-चीन सीमा मुद्दा अनसुलझा है, यह औपनिवेशिक सीमाओं, अलग-अलग धारणाओं और रणनीतिक अविश्वास की विरासत है। फिर भी, विवाद का इतिहास एक महत्वपूर्ण सबक को रेखांकित करता है: हालांकि अंतिम समाधान मायावी हो सकता है, सीमा पर शांति और स्थिरता को संवाद, संयम और विश्वास-निर्माण उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। भारत के

लिए चुनौती व्यावहारिक कूटनीति के साथ अपनी क्षेत्रीय अखंडता को संतुलित करने की है, यह सुनिश्चित करना कि अनसुलझे सीमाएं व्यापक राष्ट्रीय हितों को पटरी से न उतारें।

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: भारत-चीन सीमा मुद्दे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. मैकमोहन रेखा 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच शिमला कन्वेंशन में खींची गई थी, और चीन द्वारा स्वीकारकीगईथी।
2. अक्साई चिन क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बसा हुआ था और 1950 से पहले निरंतर भारतीय प्रशासन के अधीन था।
3. वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को पहली बार औपचारिक रूप से 1959 में चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत-चीन संबंधों को पुनर्परिभाषित करने में राजीव गांधी की 1988 की चीन यात्रा के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसने टकराव से सीमा मुद्दे के प्रबंधन में बदलाव को कैसे चिह्नित किया? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Trump's tariff war as opportunity for the Global South

Although much has been made of what the United States and U.S. President Trump are doing, it is critical for India (and the world) to dissect the *raison d'être* behind the disruptions being imposed on them today. The economic, geopolitical and technological polycrisis necessitates a strategic recalibration, to insulate ourselves and to forge a more equitable world order.

Mr. Trump's economic warfare is motivated by three imperatives. First, he is consciously pandering to America's silent majority (and not just the 'Make America Great Again' Republicans) which feels shortchanged by globalisation's nucleus, namely capital accumulation, cheap labour, the environment's colonisation and trickle-down economics. This neo-liberal status quo has caused an unprecedented concentration of wealth and power on the one hand, and mushrooming inequalities on the other. Instead of comprehensively restructuring economic paradigms and thereby redressing legitimate grievances (which the Global South also feels acutely), he has unleashed xenophobic, racist and centrifugal politics, veneered by economic populism.

Trump's motivations

Domestic politics partly explains why Mr. Trump hawkishly vilifies the liberal international order as antithetical to American interests. This has translated into sanctions on 30-plus nations and tariffs on nearly 70 (impairing the free movement of goods and ideas), the forging of trade blocs, the undermining of transnational organisations and treaties, circumscribing of foreign aid to vulnerable nations (reversing solidarity commitments dating back to the First World War) and a crackdown against immigration (impeding the free movement of labour). This 360° attack on the norms and institutions of the liberal world order is just a fig-leaf for the ruthless pursuit of sovereign self-interest.

Second, sidestepping that the tariffs are a camouflaged super-tax on American companies and consumers (who will collectively absorb 70% of tariffs costs, according to Goldman Sachs), they are designed to bolster America's economic strength by extorting nations and companies. Even though America accounts for 26% of global GDP, China, at 17%, is fast catching up (and nearly on a par with the other G-7 members, which collectively account for 20%-22% of global GDP). This is why America continues to heavily subsidise agricultural production, deepens unilateralist industrial, technology and climate change policies, bludgeons nations into making investment commitments, and strives to retrench the dollar's privileged position (including circumscribing global-currency alternatives). This coercive statecraft has historical precedent, with protectionism and punitive mercantile capitalism being leveraged to bolster economies and force sovereign nations to open markets. This hypocrisy continues and is exemplified in America pressuring India to eschew protections for the agricultural sector, while it imposes tariff



Salman Khurshid

is India's former External Affairs Minister



Pushparaj Deshpande

is Director, Samruddha Bharat Foundation

walls of 350% on tobacco products, 200% on dairy products and 120% on fruits. India's textiles, jewellery and gems, auto components and metals sectors are being severely impacted by these discriminatory tariffs. Clearly, old (imperial) habits die hard.

Third, even though tariff-weaponisation is singularly Trumpian, reversing America's perceived deindustrialisation and checking China's ascendance has bipartisan support. The escalating tariffs against India were purportedly designed to pressurise Russia to end the war with Ukraine (one of Mr. Trump's key election promises). However, despite the U.S.-Russia meeting on Ukraine, penalties against India continue (perhaps as leverage against nations pursuing multipolarity). Irrespective of when Mr. Trump can claim "peace in our time", his attention will inevitably shift to what America sees as its biggest challenge to a unipolar world – the China theatre. It is no coincidence that the tariffs also included provisions to check China's strategic influence while furthering American national security goals (as an investigation by *The Washington Post* on the U.S.'s "supplemental negotiation objectives" action memo reveals).

What New Delhi must do

These upheavals hold multiple lessons for India. Its response to the epistemic polycrisis the world faces today has to address both the substantive and the symbolic. For example, the unstated assumption that Washington sees India as a democratic counterweight to China needs to be seriously re-examined. India needs to ask the degree of geopolitical convergence it has with America given that the U.S. has renewed its vows to Pakistan (possibly to retain an inside track with China), is trying to re-hyphenate India and Pakistan, may skip the Quad Summit that India will host later this year, and inhibits American companies manufacturing in India and having advanced technology collaboration. Mr. Trump's actions have disrupted the India-U.S. partnership built painstakingly over 25 years, compelling the Bharatiya Janata Party (BJP) government to make major concessions to China to avoid a two-front problem (without any reciprocal concessions). America needs to accept that India's northern borders are live fault-lines. While India must defend its territorial integrity vigorously, for now, India must manage competition, avoid conflicts and substantively strengthen itself.

Second, the government must confront Mr. Trump more aggressively in the pursuit of India's national interest. It is no coincidence that America has not levied tariffs on China, even though their bilateral trade deficit is \$295 billion, while China imports oil from Russia and trades with Iran. This is partly because of Chinese restrictions on rare metals and magnets, which are critical to the U.S.'s defence and technology sectors. In contrast, the BJP government complied twice to American diktats, stopping oil imports from Iran and Venezuela and temporarily waiving the 11% import duty on cotton. The BJP would do well to learn that bullies only respond

to strength. Third, Prime Minister Narendra Modi's foreign policy adventurism (personalised diplomacy, manufactured diaspora events, and click-bait acronyms) have not furthered India's strategic interests and must be immediately re-calibrated. For example, the government and right-wing diaspora outfits tried in vain to ingratiate themselves to Republican legislators and right-wing influencers/lobbyists close to Mr. Trump. Likewise, BJP Ministers misread American support by myopically conflating India's economic size with strategic utility. And, equally problematically, the BJP partially eschewed non-alignment (now globally feted as multi-alignment) and sacrificed India's material interests for a symbolic seat at the high table. Sadly, the Modi-doctrine has bound China and Pakistan in an "iron-clad alliance" (creating a unified threat to India's northern flank), isolated India in its neighbourhood, put India's wealth-creators in the cross hairs of punishing tariffs, and subject American-Indians to virulent racism.

India must capitalise on disruptions

India must leverage this polycrisis to reshape the world's geo-economic and political architecture. This window could narrow after America's mid-term elections next year. Therefore, India must champion multipolarity as an alternative to both unipolarity and bipolarity. India can also capitalise on this opportunity to forge a New Economic Deal that works equitably for all nations. After all, neoliberal globalisation has not worked well, especially for those in the Global South. This has been compounded by weak and imbalanced multilateral institutions, an extreme concentration of global power and wealth in the hands of a few in the Global North, the forced reduction of taxes and high levels of sovereign debt (leading to reduced government revenues, a scaling back of state-driven functions, and limited fiscal space to invest in national developmental goals).

But to do this effectively, the government must urgently redress India's structural problems. Manufacturing is at a four-decade low, unemployment is unacceptably high, private investment is stagnant, scientific research is abysmal and public sector units are still not being re-deployed strategically (such as China's State-Owned Enterprise). The government must make concerted efforts to restore trust in economic stakeholders, spearhead policies that ensure equitable growth (without which India will not appear as an attractive market to investors), and a bold new vision.

This necessitates eschewing transactional instrumentalities, and investing time in forging relationships with multiple stakeholders within and outside government. It also means making constructive efforts to forge a bipartisan consensus both domestically and with the Global South. To expedite the realisation of India's manifest destiny, the government must shed its partisan blinkers, reach across the aisle, and lead a unified approach in the national interest.

India must move swiftly, using the unfolding polycrisis to reshape the world's geo-economic and political architecture

GS.Paper 02 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूपीएससी मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न: टैरिफ युद्ध को ग्लोबल साउथ के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। बहुध्रुवीयता में भारत के नेतृत्व की भूमिका के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

संदर्भ:

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत विघटनकारी व्यापार और टैरिफ नीतियों ने उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से एक निर्णायक प्रस्थान को चिह्नित किया। अमेरिका के आर्थिक और भू-राजनीतिक लाभ को मजबूत करने के उद्देश्य से, इन एकतरफा उपायों ने वैश्वीकरण की नाजुकता को उजागर किया और ग्लोबल साउथ के लिए जोखिम और अवसर दोनों पैदा किए। अमेरिकी संरक्षणवाद और चीन के मुखर उदय के बीच फंसे भारत के लिए चुनौती एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए विदेश नीति और आर्थिक रणनीति को पुनर्गठित करनेमेंनिहितहै।

ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के पीछे प्रेरणा

1. घरेलू राजनीति:

- वैश्वीकरण से मोहभंग हुए अमेरिका के "मूक बहुमत" सेअपीलकरना।
- आर्थिक लोकलुभावनवाद ज़ेनोफोबिया और राष्ट्रवाद में लिपटा हुआ है।

2. आर्थिक और सामरिक उद्देश्य:

- टैरिफ और सब्सिडी के माध्यम से अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करें, जबकि भागीदारों को खुले बाजारों में मजबूर करें।
- चीन की तेजी से वृद्धि के बावजूद डॉलर वर्चस्व और वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखें।
- संरक्षणवादी और व्यापारिक प्रथाओं की ऐतिहासिक निरंतरता, हालांकि अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत की गई।

3. भू-राजनीतिक गणना:

- चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने के लिए टैरिफ अर्थशास्त्र से परे विस्तारित हुए।
- उपायों ने बहुध्रुवीय पहलों को लक्षित किया और भारत के रणनीतिक स्थान को सीमित करने का प्रयास किया।
- चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में द्विदलीय सहमति ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति की दीर्घायु सुनिश्चित की।

भारत के लिए निहितार्थ

• आर्थिक प्रभाव:

- कपड़ा, आभूषण, ऑटो कंपोनेंट और धातुओं में भारतीय निर्यात टैरिफ बाधाओं कासामनाकरताहै।
- कृषि कमजोर है, अमेरिकी पाखंड अपने स्वयं के उच्च टैरिफ में स्पष्ट है, जबकि भारत पर उदारीकरण के लिए दबावडालरहाहै।

• भू-राजनीतिक उपभेद:

- ट्रंप-युग की नीतियों ने भारत-अमेरिका के 25 वर्षों को बाधित किया साझेदारी निर्माण।
- पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी पहल और भारत के सीमा मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता की कमी ने रणनीतिक बेचैनी पैदा की।
- मोदी सरकार की "व्यक्तिगत कूटनीति" दंडात्मक टैरिफ को रोकनेमेंविफलरही।

• विदेश नीति के सबक:

- अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता भारत के नीतिगत स्थान को बाधित कर सकती है।
- गुटनिरपेक्षता से दूर झुकाव ने चीन-पाकिस्तान अभिसरण में योगदान दिया है।
- प्रतीकात्मक संरक्षण के बजाय राष्ट्रीय हित के मुखर अनुसरण की आवश्यकता।

ग्लोबल साउथ के लिए अवसर**1. बहुपक्षवाद को फिर से परिभाषित करना:**

- मजबूत, संतुलित वैश्विक संस्थानों के लिए धक्का जो ग्लोबल नॉर्थ के प्रभुत्व में कम है।
- विकासशील देशों के हितों को प्रतिबिंबित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ और विश्व बैंक में सुधारों की वकालत करना।

2. चैंपियनिंग बहुध्रुवीयता:

- भारत को एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के नेता के रूप में स्थापित करना, जो अमेरिकी एकध्रुवीयता और अमेरिका-चीन द्विध्रुवीयता दोनों का विरोध करता है।

3. दक्षिण-दक्षिण एकजुटता का निर्माण:

- साझा विकासात्मक चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए ब्रिक्स, जी-77 और ग्लोबल साउथ समिट जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करना।

4. घरेलू अनिवार्यताएँ:

- विनिर्माण आधार को मजबूत करना, बेरोजगारी को संबोधित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- सरकार और आर्थिक हितधारकों के बीच विश्वास बहाल करें।
- एक बाजार और रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाने के लिए समावेशी, न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

ट्रम्प के टैरिफ युद्धों ने उदार आर्थिक व्यवस्था की नाजुकता को उजागर किया और वैश्वीकरण की विषमताओं को उजागर किया। भारत और ग्लोबल साउथ के लिये ये व्यवधान एक निष्पक्ष, बहुध्रुवीय दुनिया को आगे बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, इस विंडो को सार्थक परिवर्तन में बदलने के लिए, भारत को पहले अपनी संरचनात्मक कमजोरियों को संबोधित करना होगा, अपनी विदेश नीति को व्यक्तित्व-संचालित दृष्टिकोणों से दूर करना होगा, और समान विकास और वैश्विक एकजुटता की दृष्टि के साथ नेतृत्व करना होगा। इसलिए टैरिफ वॉर केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि रणनीतिक नवीनीकरण का आह्वान भी है।